पूरा बेंच

विविध नागरिक

ओ चिन्नाप्पा रेड्डी, भोपिंदर सिंह ढिल्लों, गुरनाम सिंह, अजीत सिंह बैंस और हरबंस लाल, जे.जे. के समक्ष

जसवंत कौर और अन्य, - याचिकाकर्ता।
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1976 की सिविल रिट याचिका संख्या 3530

17 मार्च 1977

हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट (1972 का XXVI) जैसा कि 1976 के अधिनियम XVII द्वारा संशोधित किया गया-धारा 4. 8, 9 (4) (सी) 12 और 20-ए-भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 254 (2) और सातवीं अनुसूची सूची 1, प्रविष्टियाँ 77 और 78-अधिवक्ता अधिनियम (1961 का XXV) धारा 30-हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956 का XXX) - धारा 14-किसी कानून के प्रावधान-उसमें अस्पष्टता या पारस्परिक विसंगति-चाहे उन्हें अधिकार से बाहर घोषित करने का आधार हो-ऐसी स्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य-कहा गया-अभिव्यक्ति "आश्वस्त सिंचाई" परिभाषित नहीं है _ धारा 4 (1)-चाहे अस्पष्ट हो-धारा 12 (3)-चाहे धारा 4 (1) और 8 के साथ संघर्ष में हो-धारा 12 (4)-चाहे राज्य विधानमंडल के दायरे से परे हो-धारा 9 (4) (सी)-चाहे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के प्रतिकूल हो-पंजाब भूमि सुरक्षा कार्यकाल अधिनियम के तहत छूट प्राप्त बड़े भूमि मालिकों की भूमि-ऐसे भूमि मालिकों से विक्रेता-सरकार- क्या ऐसे प्रतिशोधियों के खिलाफ अधिनियम को लागू करने से रोका गया है-धारा 20-ए-जो अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 के प्रतिकूल है और इसलिए अमान्य है।

अभिनिर्धारित किया गया कि भारत में जहां संविधान के पास 'उचित प्रक्रिया' खंड और विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कोई विधि नहीं है जिसे अधिनियमित करने की शक्ति उसके पास है, जो संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है और जो संविधान के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है, वहां कानून के प्रावधान अस्पष्ट हैं या इस आधार पर कि वे पारस्परिक रूप से असंगत हैं, उन्हें अधिकार से बाहर नहीं किया जा सकता है। किसी कानून के प्रावधानों की इस आधार पर व्याख्या करने के कार्य से असहाय और उदासीन रूप से दूर रहना कि भाषा अस्पष्ट और अस्पष्ट है और उस कारण से प्रावधानों को अधिकार से बाहर घोषित करना न्यायिक कार्य का गलत प्रतिनिधित्व है। ड्राफ्ट्समैन के दबाव की अस्पष्टता से विचलित होना न्यायिक कार्य नहीं है। अदालतों का कार्य इससे अधिक रचनात्मक होता है। प्रत्येक फोरेंसिक स्थिति के संबंध में यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विधि की भाषा की जांच करे, जिस संदर्भ में इसे बनाया गया था, विधानमंडल के इरादे की खोज करे और विधि की व्याख्या प्रभावी बनाने के लिए करे न कि व्याख्या को हतोत्साहित करने के लिए। पुनः, जहां किसी कानून के प्रावधान पारस्परिक रूप से असंगत प्रतीत होते हैं, वहां किसी कानून के प्रावधानों को उचित अर्थ देने में न्यायालय का मार्गदर्शन करने के लिए व्याख्या के कई प्रसिद्ध नियम हैं। सबसे पहले सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत है जिसके अनुसार न्यायालय को प्रत्येक भाग में सामंजस्य स्थापित करने और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करके किसी कानून के प्रावधानों में किसी भी संघर्ष से बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि प्रत्येक प्रभावी हो। फिर अन्य नियम हैं जैसे कि विशेष सामान्य पर प्रबल होगा, अंतिम पहले पर प्रबल होगा, एक संशोधन मूल आदि पर प्रबल होगा। व्याख्या के ऐसे प्रकार के नियमों की सहायता से, न्यायालय को वास्तविक विधायी इरादे का पता लगाना चाहिए और इसे अपने सामने की स्थिति पर लागू करना चाहिए। न्यायाधीश अपने कंधे नहीं झुका सकता है और इस टिप्पणी से संतुष्ट नहीं रह सकता है कि प्रावधान अपरिवर्तनीय हैं।

(पैरा 2, 3 और 4)

माना जाता है कि हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1972 की धारा 4 (1) केवल इसलिए अस्पष्ट नहीं है क्योंकि अधिनियम में "आश्वस्त सिंचाई" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। विधायिका के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह स्थिति में आने वाली प्रत्येक अभिव्यक्ति को परिभाषित करे। जहां अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है, यह मुख्य रूप से अधिनियम के तहत गठित अधिकारियों के लिए है कि वे सड़क पर आदमी द्वारा सामान्य रूप से दिए गए अर्थ, शब्दजाल की विशेष विभागीय बोलचाल में इसे दिखाए गए अर्थ, जिस संदर्भ में अभिव्यक्ति क़ानून में होती है और अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए अभिव्यक्ति की व्याख्या करें। "सुनिश्चित सिंचाई" अभिव्यक्ति प्रसिद्ध आयात की अभिव्यक्ति है जिससे भूमि राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी लोग परिचित हैं और इस अभिव्यक्ति में कुछ भी अस्पष्ट नहीं है।

(पैरा 5)

अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 4,8 और 12 (3) के उपबंधों की बारीकी से और गंभीर जांच से पता चलता है कि वे असंगत नहीं हैं और वे सभी अधिनियम की सामान्य योजना में अच्छी तरह से फिट बैठते हैं। धारा 8 को अधिनियम की धारा 12 (3) द्वारा स्पष्ट रूप से निरसित नहीं किया गया है और न ही यह कहा जा सकता है कि इसे आवश्यक निहितार्थ द्वारा निरसित किया गया है। धारा 12 (3) को 1976 के अधिनियम XVII द्वारा संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया था और धारा 8 और 12 (3) का अर्थ लगाने का एक सामंजस्यपूर्ण तरीका संशोधन अधिनियम के लागू होने की तारीख तक धारा 8 (1) को पूर्ण प्रभाव देना होगा, अर्थात धारा 12 (3) के संचालन से बाहर करना जो ऐसी तारीख तक किए गए हस्तांतरण हैं जो अधिनियम की धारा 8 (1) द्वारा संरक्षित हैं, अर्थात् (1) राज्य या केंद्र सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण (2) पेप्सू कानून या पंजाब कानून के तहत एक किरायेदार द्वारा अधिग्रहण या (3) विरासत द्वारा एक उत्तराधिकारी द्वारा अधिग्रहण। पंजाब विधि या पेप्सू विधि के अधीन अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि का अन्य अंतरण संरक्षित किया जाएगा यदि अंतरण 30 जुलाई, 1958 से पूर्व किया गया था और अन्य सभी भूमि जो धारा 8 द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी, नियत दिन से राज्य सरकार में निहित होगी। धारा 8 और 12 (3) का इस सामंजस्यपूर्ण तरीके से अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि दोनों प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके। अधिनियम की धारा 4 और धारा 12 (3) के बीच भी कोई टकराव नहीं है।

(पैरा 8, 9 और 11)

अभिनिर्धारित है कि अधिनियम की धारा 12 (4) किसी न्यायालय के किसी निर्णय को अपास्त करने या उलटने के लिए अभिप्रेत नहीं है। इसका उद्देश्य किसी निर्णय को अमान्य घोषित करना नहीं है। यह केवल यह घोषणा करता है कि किसी व्यक्ति के अधिशेष क्षेत्र को कम करने के प्रभाव वाली डिक्री को अगर नियत दिन के बाद बनाया जाता है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। जिस प्रकार अधिशेष क्षेत्र निर्धारित करने के उद्देश्य से अंतरविवोस हस्तांतरण को, जो प्रामाणिक नहीं है, नजरअंदाज किया जाना चाहिए, उसी प्रकार यह अधिनियमित किया गया है कि अधिशेष क्षेत्र को कम करने के प्रभाव वाले निर्णय को भी नजरअंदाज किया जाना चाहिए। विधायिका ने प्रामाणिक रूप से प्राप्त किए गए फरमानों के पक्ष में किसी भी बचत का प्रावधान नहीं किया है, जैसा कि सांठगांठ वाले फरमानों से अलग है, इस साधारण कारण से कि राजस्व प्राधिकरणों के लिए इस सवाल में जाना अनुचित होगा कि क्या दीवानी अदालत की डिक्री सांठगांठ वाली है। अधिनियम की धारा 12 (4) का एकमात्र प्रभाव यह है कि नियत दिन के बाद प्राप्त डिक्री को किसी व्यक्ति के अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार धारा 12 (4) किसी अन्य तरीके से निर्णय की वैधता को प्रभावित नहीं करती है। उन व्यक्तियों के अधिकार जो निर्णय के पक्षकार हैं, जैसे कि वे हैं, आपस में अप्रभावित रहते हैं। इस प्रकार अधिनियम की धारा 12 (4) को अधिनियमित करते समय, विधानमंडल ने न्यायिक कार्य का अतिक्रमण नहीं किया है और इसलिए इस प्रावधान को अधिनियमित करना उसकी विधायी क्षमता के भीतर था।

(पैरा 12)

माना जाता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 हिंदू पुरुषों और महिलाओं के स्वामित्व वाली संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित है। अधिनियम की धारा 9 (4) (सी) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा घोषित उत्तराधिकार के कानून को प्रभावित नहीं करती है। कोई तिरस्कार नहीं है, जो भी हो। एक बार जब कोई व्यक्ति संपत्ति में सफल हो जाता है, तो उसके बाद वह किसी अन्य व्यक्ति की तरह उसी कानून के अधीन संपत्ति रखता है जिसके वे अधीन हैं और जिसे समय-समय पर बनाया जा सकता है। परिवार के सदस्यों द्वारा धारित कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा से संबंधित कानून को संभवतः उत्तराधिकार से संबंधित कानून नहीं कहा जा सकता है। अतः अधिनियम की धारा 9 (4) (ग) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के प्रतिकूल नहीं है।

(पैरा 14)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी ऐसे बड़े भूस्वामी के विनिवेश के मामले में, जिसकी भूमि को उद्यान के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पंजाब प्रतिभूति भू-अधिकार अधिनियम के प्रवर्तन से छूट दी गई थी, सरकार उनके विरुद्ध हरियाणा भू-धारक सीमा अधिनियम लागू करने से इस साधारण कारण से विमुख नहीं है कि विधानमंडल या उसके अधिदेश के विरुद्ध कोई अवरोध नहीं हो सकता है। संसद को कानून बनाने से रोकने के लिए या संसद के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हुए सरकार को कार्यकारी क्षमता में पहले किए गए वादों के विपरीत अधीनस्थ कानून बनाने या सरकार को संसद के जनादेश को पूरा करने से रोकने के लिए कभी कोई रोक नहीं हो सकती है। न्यायसंगत रोक का सिद्धांत इस तरह से काम नहीं कर सकता है कि सरकार को संसद के एक अधिनियम द्वारा उस पर लगाए गए दायित्वों का निर्वहन करने से रोका जा सके या सरकार को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा सके जो कानून द्वारा निषिद्ध था या जो स्पष्ट विधायी नीति के खिलाफ था।

(पैरा 16)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के संविधान 1950 की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टियां 77 और 78 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष वकालत करने के हकदार व्यक्तियों से संबंधित हैं, अर्थात् प्रविष्टियां न केवल उन लोगों से संबंधित हैं जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में वकालत करने के हकदार हैं, बल्कि उनसे संबंधित अन्य सभी मामलों जैसे कि उनकी योग्यता, अनुशासन, अन्यत्र वकालत करने के अधिकार सहित अधिकार आदि से भी संबंधित हैं। एक अधिवक्ता का अधिकार जिसका नाम सामान्य सूची में किसी भी न्यायाधिकरण के समक्ष वकालत करने के लिए आता है या कानूनी रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति को राज्य के कानून द्वारा छीन नहीं लिया जा सकता है। इस हद तक कि धारा 20-क किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष अधिवक्ताओं की उपस्थिति को प्रतिबंधित करती है, यह अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30 के प्रतिकूल है और इसलिए अमान्य है।

(पैरा 17)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका यह प्रार्थना करती है कि वह याचिका स्वीकार करे और: -

(ए) घोषणा पत्र दाखिल करने की तारीख निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना संख्या 1629-एआर (एलए) -76/जे9985, दिनांक 2 अप्रैल 1976, अनुबंध पी-1 को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की एक रिट जारी की जाए;

(बी) अधिनियम की धारा 4,8,12 (3) 18 (7) (8) और 20-ए और नियमों के नियम 5 और 6 को संविधान के अधिकार से बाहर घोषित किया जाए और निरस्त किया जाए।

(ग) यह घोषित किया जाए कि अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) का खंड (क) केवल उन अंतरणों या निपटानों से संबंधित है जो अधिशेष क्षेत्र को कम करने का प्रभाव रखते हैं जो पंजाब प्रतिभूति भूमि कार्यकाल अधिनियम, 1953 के तहत राज्य सरकार को उपलब्ध होता।

(घ) यह घोषित किया जाए कि अधिनियम को 9 वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बावजूद, हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1976 और हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1976 और विधानमंडलों द्वारा संशोधित अधिनियम के प्रावधान मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए हमले से मुक्त नहीं हैं।

(ङ) कोई अन्य लिखित निर्देश या आदेश जो मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझा जाए, पारित किया जाए; और

(च) घोषणाओं को दाखिल करने वाली इस याचिका के निर्णय तक, पंजाब कानून के तहत अधिशेष/किरायेदारों की अनुमति वाले क्षेत्र के उपयोग को वापस लेना और आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जा सकती है और अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करना समाप्त किया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं के लिए जी. एल. नागपाल, वी. सी. नागपाल, अधिवक्ता।

एच. एन. मेहतानी, सीनियर D.A.G. हरियाणा, नौबत सिंह, A.A.G., हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

ओ चिन्नाप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति

(1) ये रिट याचिकाएं, शायद, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुसार शुरू किए गए भूमि सुधारों के हिमस्खलन के खिलाफ खड़े होने के अंतिम हताश प्रयास का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन रिट याचिकाओं में हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 (1972 का अधिनियम XXVI) के कुछ प्रावधानों के अधिकार पर सवाल उठाया गया है। इस अधिनियम को 22 दिसंबर, 1972 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 23 दिसंबर, 1972 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम को 7 सितंबर, 1974 को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया था, और इस प्रकार, यह संविधान के अनुच्छेद 31-बी के सुरक्षात्मक दायरे में आ गया और संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगतता या संक्षिप्तता के आधार पर हमले से मुक्त हो गया। हालांकि, 9 सितंबर, 1974 को, सरोज कुमारी बनाम हरियाणा राज्य, 1975 पी.एल.आर. 407. इस न्यायालय की एक खंडपीठ, जो स्पष्ट रूप से नौवीं अनुसूची में अधिनियम को शामिल करने से अनजान थी, ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वे प्रावधान संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को आहत करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 31-ए द्वारा भी नहीं बचाया गया था, क्योंकि वे प्रावधान जो मुख्य रूप से 'परिवार इकाई' से संबंधित हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (बी) और (सी) को आगे बढ़ाने में नहीं कहा जा सकता है। डिवीजन बेंच ने सुच्चा सिंह बाजवा बनाम पंजाब राज्य 1974 पी.एल.आर. 273. मामले में इस अदालत की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जहां पंजाब भूमि सुधार अधिनियम के समान प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था। सुच्चा सिंह बाजवा बनाम पंजाब राज्य मामले में पूर्ण पीठ के फैसले को तब से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं. 1975 का 1040। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पंजाब भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 31-ए और अनुच्छेद 31-बी दोनों द्वारा सुरक्षित हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए और इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि डिवीजन बेंच ने नौवीं अनुसूची में हरियाणा अधिनियम को शामिल करने पर ध्यान नहीं दिया, सरोज कुमारी बनाम हरियाणा राज्य में निर्णय को अब अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है। लेकिन, श्री आनंद स्वरूप ने तर्क दिया कि हरियाणा अधिनियम अव्यवहारिक था क्योंकि इसके कुछ प्रावधान अस्पष्ट और पारस्परिक रूप से असंगत थे। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रावधान जो अस्पष्ट, असंगत थे और इसलिए अव्यावहारिक थे, उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए और न तो अनुच्छेद 31-ए और न ही संविधान का अनुच्छेद 31-बी ऐसे प्रावधानों को बचा सकता है। उन्होंने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि सरोज कुमारी के मामले में, डिवीजन बेंच ने यह अभिनिर्धारित करने के अलावा कि अधिनियम के प्रावधान संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, हरियाणा अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त कारण भी दिए: -

"याचिका में कहा गया है, 'सुच्चा सिंह बाजवा के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले में बताए गए कारणों के अलावा, परिवार के अनुमेय क्षेत्र से संबंधित अधिनियम के प्रावधान अस्पष्टता और अनिश्चितता के दुष्प्रभाव से ग्रस्त हैं और अपूर्ण और अव्यवहारिक होने के कारण निरस्त किए जाने के योग्य हैं।"

हमने श्री आनंद स्वरूप से सीधा सवाल किया कि क्या, सरोज कुमारी के मामले के अलावा, वह इस दलील का समर्थन करने के लिए किसी न्यायिक मिसाल या अकादमिक प्राधिकरण का हवाला दे सकते हैं कि किसी क़ानून के प्रावधानों को ऐसे आधारों पर अधिकार से बाहर घोषित किया जा सकता है। श्री आनंद स्वरूप ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि कोई नहीं था। हालाँकि, उन्होंने क़ानून के एक हिस्से को असंवैधानिक के रूप में निरस्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सादृश्य पर भरोसा किया, जहाँ पूरे क़ानून को रद्द कर दिया जाना है यदि जो बचा है उसे क़ानून के परिवर्तन और संशोधनों के बिना लागू नहीं किया जा सकता है। हमें नहीं लगता कि स्थिति कम से कम

समान है। 'अनुप्रयोग में पृथकता' या 'प्रवर्तन में पृथकता' के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस तर्क पर विचार करते समय मान्यता दी गई है कि किसी कानून को पूरी तरह से शून्य घोषित किया जाना चाहिए यदि वह आंशिक रूप से संवैधानिक रूप से अमान्य है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि वैध और अमान्य प्रावधान अलग और अलग हैं और जो अमान्य है उसे बाहर निकालने के बाद जो बचा है वह अपने आप में बाकी से स्वतंत्र एक पूर्ण संहिता है, तो इसे बरकरार रखा जाएगा, इसके बावजूद कि बाकी अप्रवर्तनीय हो गए हैं। दूसरी ओर, यदि वैध और अमान्य उपबंधों को इतना अटूट रूप से मिलाया जाता है कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, या यदि वे एक एकल एकीकृत योजना का भाग हैं जिसका उद्देश्य समग्र रूप से क्रियाशील होना है या यदि जो बचा है वह इतना पतला और कटा हुआ है कि विधायिका द्वारा जो इरादा किया गया था उससे सार रूप में अलग है, तो कानून के हिस्से की अयोग्यता के परिणामस्वरूप संपूर्ण रूप से विफल हो जाएगा। लागू किया जाने वाला अंतिम परीक्षण यह है कि क्या विधायिका ने वैध भाग को अधिनियमित किया होगा यदि उसे पता होता कि शेष क़ानून अमान्य था। इस प्रकार, जहां पृथकता का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है, वहां असंवैधानिकता का दोष जिससे एक क़ानून का हिस्सा पीड़ित होता है, खुद को पूरे क़ानून से जोड़ता है। यह नियम संभवतः लागू नहीं हो सकता है जहां क़ानून का कोई भी हिस्सा असंवैधानिक नहीं है।

(2) भारत में, जहां हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह संविधान में 'उचित प्रक्रिया' खंड नहीं है, यह अकल्पनीय है कि विधायिका द्वारा अधिनियमित एक कानून, जिसे उसे अधिनियमित करने की शक्ति है, जो संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है और जो संविधान के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है, को या तो इस आधार पर अधिकार से बाहर घोषित किया जा सकता है कि क़ानून के प्रावधान अस्पष्ट हैं या इस आधार पर कि वे पारस्परिक रूप से असंगत हैं। अमृतसर नगरपालिका बनाम पंजाब राज्य के मामले में, पंजाब उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर विचार करते हुए कि 'अस्पष्ट, अनिश्चित और अस्पष्ट' कानून को निरस्त किया जाना था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहाः -

"लेकिन यह नियम कि एक सक्षम विधायिका के अधिनियम को अस्पष्टता के आधार पर न्यायालयों द्वारा" निरस्त "किया जा सकता है, हमारी संवैधानिक प्रणाली के लिए अलग है। पंजाब राज्य का विधानमंडल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 28 के अनुसार "मेलों" के संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम था। भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा किसी विधि को अमान्य घोषित किया जा सकता है यदि विधानमंडल के पास विधि अधिनियमित करने की कोई शक्ति नहीं है या यह कि विधि संविधान के भाग III में गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है या किसी भी संवैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत है, लेकिन इस आधार पर नहीं कि यह अस्पष्ट है। यह सत्य है कि खंड सी. कॉनली बनाम सामान्य निर्माण कंपनी, (1926) 70 लॉ एड 322 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

"एक क़ानून जो या तो किसी कार्य को करने से रोकता है या उसकी शर्तों को इतना अस्पष्ट करता है कि सामान्य बुद्धि के लोगों को इसके अर्थ का अनुमान लगाना चाहिए और इसके अनुप्रयोग के बारे में भिन्न होना चाहिए, कानून की उचित प्रक्रिया की पहली अनिवार्यता का उल्लंघन करता है।" लेकिन अमेरिकी न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित नियम हमारे संवैधानिक ढांचे के तहत लागू नहीं होता है। इस नियम को 5 वें और 14 वें संशोधनों द्वारा अमेरिकी संविधान में शामिल "उचित प्रक्रिया खंड" का एक आवश्यक माना जाता है। भारत में न्यायालयों के पास इस आधार पर किसी क़ानून को अमान्य घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है कि यह "कानून की उचित प्रक्रिया" का उल्लंघन करता है। हमारे संविधान के तहत, कानून की उचित प्रक्रिया की कसौटी संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों पर लागू नहीं की जा सकती है।

(3) हमारी राय में यह न्यायिक कार्य की गलत व्याख्या है कि किसी कानून के प्रावधानों की व्याख्या करने के कार्य से इस आधार पर असहाय और उदासीन रूप से दूर रहना कि भाषा अस्पष्ट और अस्पष्ट है और उस कारण से प्रावधानों को अधिकार से बाहर घोषित करना है। यह न्यायिक कार्य नहीं है, जैसा कि हम इसे देखते हैं, ड्राफ्ट्समैन की अभिव्यक्ति की अस्पष्टता से विचलित होना। हमारा कार्य इससे अधिक रचनात्मक है। प्रत्येक फोरेंसिक स्थिति के संबंध में, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कानून की भाषा, जिस संदर्भ में इसे बनाया गया था, की जांच करे,

विधायिका के इरादे की खोज करे और कानून की व्याख्या प्रभावी बनाने के लिए करे न कि विधायी इरादे को विफल करने के लिए। कानून की व्याख्या करें, हमें करना चाहिए, और हम हमेशा व्याख्या के प्रसिद्ध सिद्धांतों की सहायता कर सकते हैं। सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम आशेर में, 1949(2) All. E.P. 155. लॉर्ड डेनिंग ने कहाः -

"एक न्यायाधीश केवल हाथ जोड़कर ड्राफ्ट्समैन को दोषी नहीं ठहरा सकता है। उसे संसद के इरादे को खोजने के रचनात्मक कार्य पर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, और उसे ऐसा न केवल क़ानून की भाषा से करना चाहिए, बल्कि उन सामाजिक स्थितियों पर भी विचार करना चाहिए जिन्होंने इसे जन्म दिया और जिस शरारत को इसे सुधारने के लिए पारित किया गया था, और फिर उसे लिखित शब्द का पूरक होना चाहिए ताकि विधायिका के इरादे को 'बल और जीवन' दिया जा सके।"

लॉर्ड डेनिंग ने अपने सुखद विशिष्ट तरीके से आगे कहा कि एक न्यायाधीश को उस सामग्री को नहीं बदलना चाहिए जिसमें 1 एक्ट बुना गया है, वह क्रीज को इस्त्री कर सकता है और उसे करना चाहिए। स्वर्गीय प्रोफेसर लास्की शायद सही थे जब उन्होंने कहा, "व्याख्या की विधि कम विश्लेषणात्मक और चरित्र में अधिक कार्यात्मक होनी चाहिए; इसे कार्रवाई में विधायी सिद्धांत के प्रभाव की खोज करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उस सामाजिक मूल्य को पूरा महत्व दिया जा सके जिसे प्राप्त करने का इरादा है।"

(4) जहां किसी कानून के प्रावधान पारस्परिक रूप से असंगत प्रतीत होते हैं, वहां किसी कानून के प्रावधानों को उचित अर्थ देने में न्यायालय का मार्गदर्शन करने के लिए व्याख्या के कई प्रसिद्ध नियम हैं। सबसे पहले सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत है जिसके अनुसार न्यायालय को प्रत्येक भाग को सामंजस्यपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बनाने का प्रयास करके कानून के प्रावधानों में किसी भी संघर्ष से बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि प्रत्येक प्रभावी हो। फिर अन्य नियम हैं जैसे कि विशेष सामान्य पर प्रबल होगा, अंतिम पहले पर प्रबल होगा, एक संशोधन मूल आदि पर प्रबल होगा। व्याख्या के ऐसे और संबंधित नियमों की सहायता से, न्यायालय को सही विधायी इरादे का पता लगाना चाहिए और इसे अपने सामने की स्थिति पर लागू करना चाहिए। न्यायाधीश अपने कंधे नहीं झुका सकता है और इस टिप्पणी से संतुष्ट नहीं रह सकता है कि प्रावधान अपरिवर्तनीय हैं।

(5) अब हम इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या इस कथन का कोई औचित्य है कि कुछ प्रावधान अस्पष्ट और पारस्परिक रूप से असंगत हैं। अनुमेय क्षेत्र के निर्धारण के प्रयोजन के लिए धारा 4 (1) भूमि को तीन श्रेणियों में विभाजित करती हैः (i) एक वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम सुनिश्चित सिंचाई के तहत भूमि, (ii) एक वर्ष में कम से कम एक फसल उगाने में सक्षम सुनिश्चित सिंचाई के तहत भूमि, (iii) बगीचे के तहत भूमि सहित अन्य सभी प्रकार की भूमि। धारा 4 (5) आगे (i) के तहत आने वाली भूमि को दो वर्गों में विभाजित करती हैः (i) निजी स्वामित्व वाले ट्यूबवेल, पंपिंग सेट आदि से सिंचाई के तहत भूमि। और (ii) नहरों या राज्य ट्यूबवेलों से सिंचाई के तहत भूमि। यह कहा गया था कि धारा 4 (1) जो कि महत्वपूर्ण धारा है, अस्पष्ट थी क्योंकि अधिनियम में "आश्वस्त सिंचाई" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया था। हम नहीं समझते कि विधानमंडल के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी कानून में होने वाली प्रत्येक आवश्यकता को परिभाषित करे। जहां किसी अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है, यह मुख्य रूप से अधिनियम के तहत गठित अधिकारियों के लिए है कि वे सड़क पर रहने वाले व्यक्ति द्वारा सामान्य रूप से दिए गए अर्थ, विशेष विभागीय बोलचाल या शब्दजाल में इसे दिए गए अर्थ, जिस संदर्भ में अभिव्यक्ति क़ानून में होती है और अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए अभिव्यक्ति का हस्तक्षेप करें। हमें इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि 'सुनिश्चित सिंचाई' की अभिव्यक्ति एक प्रसिद्ध आयात की अभिव्यक्ति है जिससे भूमि राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी लोग परिचित हैं। हम संतुष्ट हैं कि 'सुनिश्चित सिंचाई' की अभिव्यक्ति में कुछ भी अस्पष्ट नहीं है। हम इस स्तर पर अभिव्यक्ति को परिभाषित या व्याख्या करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। हम ऐसा तब करना पसंद करते हैं जब अधिनियम के तहत गठित अधिकारियों ने अभिव्यक्ति पर अपनी व्याख्या रखी हो और मामला अनुमोदन के साथ हमारे विचार के लिए सामने आए। वर्तमान उद्देश्य के लिए यह कहना पर्याप्त है कि हमें अभिव्यक्ति कम से कम अस्पष्ट नहीं लगती है।

(6) यह भी है कि हम इस समय अनुमेय क्षेत्र से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों और अनुमेय क्षेत्र निर्धारित करने के उद्देश्य से मूल्यांकन की विधि निर्धारित करने वाले नियमों की जांच करते हैं। धारा 4 (1) अनुमेय क्षेत्र को इस प्रकार निर्धारित करती है (क) वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम सुनिश्चित सिंचाई के तहत भूमि के मामले में 7.25 हेक्टेयर, (ख) वर्ष में कम से कम एक फसल उगाने में सक्षम सुनिश्चित सिंचाई के तहत भूमि के मामले में 10.9 हेक्टेयर और (ग) बागों के तहत भूमि सहित अन्य सभी प्रकार की भूमि के मामले में 21.8 हेक्टेयर। धारा 4 (5) में आगे यह उपबंध किया गया है कि निजी स्वामित्व वाले ट्यूबवेलों, पंपिंग सेटों आदि से सिंचाई के अधीन पांच हेक्टेयर भूमि उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम में परिभाषित नहरों से या पंजाब ट्यूबवेल अधिनियम में परिभाषित राज्य ट्यूबवेलों से सिंचाई के अधीन चार हेक्टेयर भूमि के बराबर होगी। धारा 4 (4) में मूल रूप से यह उपबंध किया गया है कि अनुज्ञेय क्षेत्र का निर्धारण 'सिंचाई की तीव्रता', सिंचाई के साधनों के स्वामित्व और बंजर, सेम, थुर या कल्लर जैसी मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित तरीके से गणना किए जाने वाले मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, बशर्ते कि कुल भौतिक जोत 21.8 हेक्टेयर से अधिक न हो। हालाँकि, धारा 4 (4) को 1976 के अधिनियम XVII द्वारा संशोधित किया गया था और "और बंजर, सेम, थुर या कल्लर जैसी मिट्टी के प्रकार" शब्दों को हटा दिया गया था और उनके स्थान पर "और ऐसे अन्य तथ्य जो निर्धारित किए जा सकते हैं" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया था। हम यहां उल्लेख कर सकते हैं कि 1976 के अधिनियम XVII को भी संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अधिनियम की धारा 4 (4) में निर्धारित गणना के तरीके को निर्धारित करते हुए नियम बनाए गए हैं। एक वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम और धारा 4 (1) (ए) में उल्लिखित नहर या राज्य ट्यूबवेल द्वारा सिंचित सुनिश्चित सिंचाई के तहत भूमि को 'ए' श्रेणी की भूमि माना जाता है। एक वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम और धारा 4 (1) (ए) के साथ धारा 4 (5) में उल्लिखित निजी ट्यूबवेल या पंपिंग सेट द्वारा सिंचित सुनिश्चित सिंचाई के तहत भूमि को 'एए' श्रेणी की भूमि माना जाता है। धारा 4 (1) (बी) में उल्लिखित वर्ष में कम से कम एक फसल उगाने में सक्षम सुनिश्चित सिंचाई के तहत भूमि को 'बी' कैटेगरी भूमि माना जाता है। धारा 4 (1) (सी) में उल्लिखित बागों के तहत भूमि सहित अन्य सभी प्रकार की भूमि को 'सी' श्रेणी की भूमि माना जाता है। नियम 5 (1) 'ए' श्रेणी की भूमि की एक इकाई को 'एए' श्रेणी की भूमि की 1.25 इकाइयों, 'बी' श्रेणी की भूमि की 1.5 इकाइयों या 'सी' श्रेणी की भूमि की 3 इकाइयों के बराबर करता है। मूल रूप से बनाए गए नियम 5 (2) में मूल्यांकन के उद्देश्य से 'सिंचाई की तीव्रता' को ध्यान में रखने के लिए कोई सूत्र निर्धारित नहीं किया गया था। इसने भूमि की मिट्टी की प्रकृति को ध्यान में नहीं रखा। इसमें कुछ अन्य दोष भी थे। इसे सरोज कुमारी के मामले में धारा 4 के अधिकार से बाहर घोषित किया गया था। इसके बाद, इसे हटा दिया गया और इसके स्थान पर नया नियम 5 (2) प्रतिस्थापित किया गया। जबकि धारा 4 (4) में भी संशोधन किया गया था जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था। नया नियम 5 (2) 'सिंचाई की तीव्रता' को ध्यान में रखते हुए विस्तृत प्रावधान करता है। नियम 5 (2) (क) में यह उपबंध है कि जहां भूमि बारहमासी नहर द्वारा सिंचाई के लिए अधिदेशित है, वहां ऐसी भूमि के क्षेत्र को अनुसूची 'क' में ऐसी नहर के विरुद्ध विनिर्दिष्ट सिंचाई तीव्रता अनुपात के आधे से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त आंकड़ा 'क' श्रेणी की भूमि के रूप में माना जाएगा और ऐसी भूमि का शेष क्षेत्र 'ग' श्रेणी की भूमि के रूप में माना जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां इस प्रकार अधिदेशित भूमि का संपूर्ण या भाग राजस्व अभिलेख में थुर या कल्लर के रूप में वर्णित है, इस प्रकार वर्णित क्षेत्र को अनुसूची 'क' में ऐसी नहर के विरुद्ध निर्दिष्ट सिंचाई तीव्रता अनुपात के आधे से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त आंकड़े को 'बी' श्रेणी की भूमि माना जाएगा और ऐसी शेष भूमि को 'सी' श्रेणी की भूमि माना जाएगा। इसी तरह, सरकारी ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई के लिए गैर-बारहमासी या प्रतिबंधित बारहमासी नहर भूमि द्वारा सिंचाई के लिए भूमि और निजी स्वामित्व वाले ट्यूबवेल या पंपिंग सेट, कुओं या अन्य स्रोतों से निकाले गए पानी द्वारा नहर के पानी या सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई के लिए भूमि के लिए विस्तृत प्रावधान किया गया है। नियमों में कई चित्र भी दिए गए हैं। श्री आनंद स्वरूप ने तर्क दिया कि नियम 5 अधिनियम की धारा 4 के विपरीत था, क्योंकि इसमें अधिनियम की धारा 4 (4) द्वारा निर्धारित मिट्टी के प्रकार को ध्यान में नहीं रखा गया था। उन्होंने सरोज कुमारी के मामले में निर्णय पर भरोसा किया। सरोज कुमारी के मामले में, विद्वान न्यायाधीश धारा 4 (4) पर विचार कर रहे थे क्योंकि यह 1976 के अधिनियम XVII द्वारा संशोधित किया गया था। उस समय, धारा 4 (4) में "बंजर, सेम, थुर या कल्लर जैसी मिट्टी" शब्द आए थे। उन्हें 1976 के अधिनियम XVII द्वारा धारा 4 (4) से हटा दिया गया था। इसने इस मौलिक आपत्ति को दूर कर दिया कि नियम 5 अति-प्रतिकूल था क्योंकि इसमें धारा 4 (4) द्वारा निर्धारित मिट्टी की प्रकृति को ध्यान में नहीं रखा गया था। नियम 5 के संबंध में

डिवीजन बेंच की अन्य आलोचना नियम 5 के दूसरे खंड के खिलाफ निर्देशित की गई थी, जिसमें 'अबियाना चार्ज करने के लिए नहर विभाग द्वारा संचालित गिरदावरी के रिकॉर्ड' का उल्लेख किया गया था। यह कहा गया था कि नहर विभाग द्वारा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था और इससे पहले, नियम 5 को निरस्त किया जा सकता था। उस खामी को भी ठीक कर लिया गया है। डिवीजन बेंच के निर्णय के समय नियम 5 (2) को हटा दिया गया है और वर्तमान नियम 5 (2) को पेश किया गया है। यह सरोज कुमारी के मामले में डिवीजन बेंच द्वारा बताई गई किसी भी कमजोरी से पीड़ित नहीं है। नियम 5, जैसा कि अब है, अंतर-धारा धारा 4 है और मान्य है।

(7) अब अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बीच विसंगतियों के आधार पर हमले पर आते हुए, यह लगभग विशेष रूप से धारा 12 (3) (1976 के अधिनियम XVII द्वारा प्रस्तुत) के खिलाफ निर्देशित किया गया था, जो प्रावधान, यह कहा गया था कि अधिनियम की धारा 4 (1) और धारा 8 के साथ संघर्ष में था। धारा 4 (1) में भूमि मालिक के साथ-साथ किरायेदार के संबंध में अनुमेय क्षेत्र के निर्धारण का प्रावधान है। धारा 8 में अधिनियम के संचालन से कुछ स्थानान्तरणों को बचाने का प्रभाव है। पूरी धारा 8 (1) को निकालना उपयोगी है। वह इस प्रकार हैः -

"8. कुछ स्थानांतरण या स्वभाव अधिशेष क्षेत्र को प्रभावित नहीं करते हैं -

(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या पेप्सू विधि या पंजाब विधि के अधीन किसी किरायेदार द्वारा या उत्तराधिकार द्वारा किसी उत्तराधिकारी द्वारा अधिग्रहित भूमि के मामले को छोड़कर, निम्नलिखित से अधिक भूमि का कोई अंतरण या व्ययन नहीं किया जाएगाः -

(क) 30 जुलाई, 1958 के पश्चात् पेप्सू विधि या पंजाब विधि के अधीन अनुज्ञेय क्षेत्र और

(ख) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय क्षेत्र, नियत दिन के पश्चात् एक प्रामाणिक अंतरण या स्वभाव को छोड़कर, उपर्युक्त अधिनियमों के अधीन राज्य सरकार के उस अधिशेष क्षेत्र के अधिकार को प्रभावित करेगा जिसका वह हकदार होगा, लेकिन ऐसे अंतरण के लिएः

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसे भूमि के ऐसे हस्तांतरण या निपटान के तहत लाभ प्राप्त हुआ है, वह इसे पुनर्स्थापित करने के लिए बाध्य होगा, या उस व्यक्ति को इसके लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा जिससे उसने इसे प्राप्त किया था।"

धारा 12 (1) में यह उपबंध किया गया है कि किसी भूस्वामी का अधिशेष क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित किया गया समझा जाएगा और ऐसे क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के सभी अधिकार, अधिकार या हित समाप्त हो जाएंगे। राज्य सरकार में निहित ऐसे सभी अधिकार अन्याय से मुक्त हैं। धारा 12 (2) में यह प्रावधान किया गया है कि अपने अधिशेष क्षेत्र में किरायेदार का अधिकार और हित जो भूमि मालिक के अनुमेय क्षेत्र के भीतर शामिल है, समाप्त हो जाएगा। धारा 12 (3), जिसके विरुद्ध, जैसा कि हमने कहा, हमला केंद्रित था, इस प्रकार हैः -

"पंजाब कानून के तहत अधिशेष या किरायेदार का अनुमेय क्षेत्र घोषित क्षेत्र और पेप्सू कानून के तहत अधिशेष घोषित क्षेत्र, जो अब तक राज्य सरकार में निहित नहीं है, को नियत दिन से राज्य सरकार में निहित माना जाएगा और जो क्षेत्र पंजाब कानून या पेप्सू कानून के तहत तय की जाने वाली लंबित कार्यवाही में घोषित किया जा सकता है, उसे ऐसी घोषणा की तारीख से राज्य सरकार में निहित माना जाएगा।"

विद्वत वकील का निवेदन था कि धारा 12 (3) और धारा 4 (1) और धारा 8 के पहले के दो प्रावधानों के बीच स्पष्ट विसंगति थी। यह कहा गया था कि जहां धारा 4 (1) में किरायेदार के अनुज्ञेय क्षेत्र के निर्धारण का भी उपबंध किया गया है, वहीं धारा 12 (3) में यह विहित किया गया है कि पंजाब विधि के अधीन किरायेदार का अनुज्ञेय क्षेत्र, जो अब तक सरकार में निहित नहीं था, नियत दिन से राज्य सरकार में निहित समझा जाएगा। तर्क यह था कि यदि भूमि सरकार में निहित है तो अधिनियम के तहत किरायेदार के अनुमेय क्षेत्र को निर्धारित करने का क्या मतलब

है? यह फिर से कहा गया कि जबकि धारा 8 ने अधिनियम के संचालन से कुछ हस्तांतरणों को बचाया, धारा 12 (3) ने उन हस्तांतरणकर्ताओं के पक्ष में ऐसा कोई अपवाद नहीं बनाया। उदाहरण के लिए: यह कहा गया था कि जिस भूमि को पंजाब भू-अधिकार सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित किया गया था, लेकिन जिसे केंद्र सरकार द्वारा अप्रयुक्त और बाद में अधिग्रहित किया गया था, वह केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण के बावजूद राज्य सरकार की धारा 12 (3) के तहत निहित होगी। इसी प्रकार, पंजाब प्रतिभूति भू-अधिकार अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अधीन किरायेदार द्वारा भू-स्वामित्व वाली भूमि, किरायेदार द्वारा खरीद के होते हुए भी, धारा 12 (3) के अधीन राज्य सरकार में निहित होगी। उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरण के मामले में भी ऐसा ही है। यहां तक कि 20 जुलाई, 1958 (धारा 8 (1) (ए) में उल्लिखित तिथि) से पहले किए गए हस्तांतरण को भी बचाया नहीं जाएगा, अगर वे पंजाब प्रतिभूति भूमि कार्यकाल अधिनियम के तहत अधिशेष क्षेत्र या किरायेदार के अनुमेय क्षेत्र की घोषणा के बाद किए गए थे।

(8) धारा 4 और 8 के प्रावधान, विशेष रूप से धारा 8, पहली धारणा में धारा 12 (3) के प्रावधानों के साथ असंगत प्रतीत होते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, यह हमारा पहला कर्तव्य है कि हम प्रत्येक भाग को सामंजस्य और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करके संघर्ष से बचने का प्रयास करें ताकि प्रत्येक प्रभावी हो। प्रावधानों की एक करीबी और आलोचनात्मक जांच से पता चलता है कि वे अपरिवर्तनीय नहीं हैं और वे सभी अधिनियम की सामान्य योजना में अच्छी तरह से फिट बैठते हैं। अधिनियम की धारा 12 (3) द्वारा धारा 8 को स्पष्ट रूप से निरसित नहीं किया गया है और न ही यह कहा जा सकता है कि यह आवश्यक निहितार्थ द्वारा निरसित किया गया था। धारा 12 (3) को 1976 के अधिनियम XVII द्वारा संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। संशोधन अधिनियम की धारा 1 (2) द्वारा यह माना जाता है कि यह 23 दिसम्बर, 1972 को प्रवृत्त हुआ था। धारा 8 और 12 (3) का अर्थ लगाने का एक सामंजस्यपूर्ण तरीका 23 दिसंबर, 1972 तक धारा 8 (1) को पूरी तरह से प्रभावी बनाना होगा। अर्थात् 23 दिसम्बर, 1972 तक किए गए अंतरण जो अधिनियम की धारा 8 (1) द्वारा संरक्षित हैं, अर्थात् (1) राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, (2) पेप्सू विधि या पंजाब विधि के अधीन किसी किरायेदार द्वारा अधिग्रहण, या (3) उत्तराधिकार द्वारा किसी उत्तराधिकारी द्वारा अधिग्रहण, धारा 12 (3) के प्रवर्तन से अपवर्जित करने के लिए। पंजाब कानून या पेप्सू कानून के तहत अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि के अन्य हस्तांतरण को संरक्षित किया जाएगा यदि हस्तांतरण 30 जुलाई, 1958 से पहले किया गया था। हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि धारा 8 और 12 (3) का इस सामंजस्यपूर्ण तरीके से अर्थ क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए ताकि दोनों प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके। समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों से हम पाते हैं कि सरकार ने भी प्रावधानों का अर्थ इसी तरह से लगाया है। मेमो नं. 5726-एआर (आईए)-76/28319 दिनांक 15 सितंबर, 1976 को वित्तीय आयुक्त और सरकार, हरियाणा, राजस्व विभाग के सचिव द्वारा अंबाला और हिसार डिवीजनों आदि के आयुक्तों को संबोधित करते हुए कहा गया हैः -

" पंजाब कानून की धारा 18 और पेप्सू कानून की धारा 22 के तहत पात्र किरायेदारों द्वारा पहले से ही खरीदे गए अधिशेष क्षेत्र को कानूनी रूप से उपयोग किया गया माना जाना चाहिए और इसलिए, हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 की धारा 12 (3) के तहत राज्य सरकार में निहित नहीं होना चाहिए। केवल ऐसा अप्रयुक्त अधिशेष क्षेत्र जिसे पंजाब कानून या पेप्सू कानून के तहत पात्र किरायेदारों/व्यक्तियों द्वारा नहीं खरीदा गया था, हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 की धारा 12 (3) के तहत नियत दिन से राज्य सरकार में निहित माना जाना चाहिए और राज्य सरकार के पक्ष में तुरंत उत्परिवर्तित किया जा सकता है और पात्र व्यक्तियों को ऐसा क्षेत्र आवंटित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई अधिशेष और अन्य क्षेत्र योजना, 1976 के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है। "

एक बार फिर मेमो नं. 6632-ए. आर. (II)-76/33309, दिनांक 29 अक्टूबर, 1976 को यह कहा गया हैः

" सरकार के संज्ञान में यह आया है कि हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 की धारा 8 और धारा 12 (3) के प्रावधानों की सही व्याख्या करने में कुछ समझ की कमी है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि

हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 की धारा 8 अन्य बातों के साथ-साथ 30 जुलाई, 1958 के बाद बनाए गए पुराने अधिनियमों के तहत अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि के हस्तांतरण और विस्थापन को प्रतिबंधित करती है। इसलिए, 30 जुलाई, 1958 से पहले बनाए गए पंजाब कानून या पेप्सू कानून के तहत अधिशेष क्षेत्र के हस्तांतरण या निपटान को कानून द्वारा नियमित किया जाता है या दूसरे शब्दों में वे अधिशेष पूल को प्रभावित करेंगे। इसके परिणामस्वरूप, अधिशेष क्षेत्र जिसे 30 जुलाई, 1958 से पहले भूमि-मालिकों द्वारा अंतरित या निपटाया गया था, हरियाणा भूमि धारक सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 12 (3) के तहत राज्य सरकार में निहित नहीं होगा और इसलिए, ऐसे क्षेत्र का उपयोग अधिशेष और अन्य क्षेत्र योजना, 1976 के उपयोग के अनुसार नहीं किया जा सकता है। "

(9) विद्वान सहायक महाधिवक्ता श्री नानबत सिंह ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि हमें धारा 8 और धारा 12 (3) को उसी तरीके से समन्वित करना चाहिए जैसा हमने किया है, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि जिस तारीख तक हमारे द्वारा पहले निर्दिष्ट तीन श्रेणियों (1) (2) और (3) के हस्तांतरण को मान्यता दी जानी चाहिए, वह नियत दिन (24 जनवरी, 1971) होना चाहिए, न कि वह तारीख जिस पर धारा 12 (3) लागू हुई थी। हम सहमत नहीं हैं। 1976 के अधिनियम XVII की धारा 1 (2) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यह अधिनियम 23 दिसंबर, 1972 को लागू होगा। हमें इसे कुछ अर्थ और प्रभाव देना चाहिए। हमारे विचार में, धारा 8 पर 23 दिसंबर, 1972 से लागू होने वाली धारा 12 (3) का प्रभाव यह है कि 23 दिसंबर, 1972 तक हमारे द्वारा निर्दिष्ट तीन श्रेणियों के हस्तांतरण को धारा 12 (3) के संचालन से बाहर रखा जाएगा कि पंजाब या पेप्सू कानून के तहत अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि का हस्तांतरण यदि 30 जुलाई, 1958 से पहले किया जाता है तो संरक्षित किया जाएगा और यह कि धारा 8 द्वारा छोड़कर अन्य सभी भूमि नियत दिन से राज्य सरकार में निहित होगी।

(10) हम यहां यह उल्लेख कर सकते हैं कि यद्यपि धारा 8 के अधीन, पंजाब विधि के अधीन घोषित अधिशेष क्षेत्र से अंतरणों को केवल 30 जुलाई, 1958 तक ही मान्यता प्राप्त है, तथापि सरकार ने कुछ शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से 15 अप्रैल, 1966 तक अंतरणों को मान्यता प्रदान की है। मेमो नं. इस संबंध में 5726-एआर (एलए)-76/28819, दिनांक 15 सितंबर, 1976 का उल्लेख किया जा सकता है।

(11) धारा 4 और धारा 12 (3) के बीच कथित संघर्ष के संबंध में अधिनियम के अन्य प्रावधानों की जांच से पता चलेगा कि सत्य और सार में कोई संघर्ष नहीं है। धारा 15 (1) घोषित करती है कि धारा 12 के तहत अधिग्रहित या निहित अधिशेष क्षेत्र राज्य सरकार के निपटान में होगा। धारा 15 (2) राज्य सरकार को अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए एक कर्तव्य का आदेश देती है, जिसमें किरायेदारों सहित व्यक्तियों के विभिन्न श्रेणियों को भूमि का आवंटन किया जाता है। धारा 15 (2) के परंतुक में स्पष्ट रूप से किरायेदारों के विभिन्न कैटेगरी को भूमि के आवंटन का प्रावधान है। वे इस प्रकार हैं:

" (i) पंजाब कानून या पेप्सू कानून, जैसा भी मामला हो, के तहत किरायेदार के अनुमेय क्षेत्र के रूप में घोषित एक किरायेदार धारक भूमि को उसके द्वारा धारित क्षेत्र की सीमा या इस अधिनियम के तहत अनुमेय क्षेत्र, जो भी कम हो, के लिए भूमि आवंटित की जा सकती है;

(ii) एक किरायेदार जिसे पंजाब कानून या पेप्सू कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिशेष क्षेत्र में भूमि का आवंटन और कब्जा दिया गया था, उसे इस तरह से आवंटित क्षेत्र की सीमा तक भूमि आवंटित की जा सकती है;

(iii) पंजाब विधि की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) या पेप्सू विधि की धारा 7 क की उपधारा (1) के अधीन उसके विरुद्ध पारित किसी निष्कासन आदेश या डिक्री के परिणामस्वरूप निष्कासन के लिए दायी किसी किरायेदार को पंजाब विधि की धारा 9 क या पेप्सू विधि की धारा 7 क, यथास्थिति, में उल्लिखित क्षेत्र की सीमा तक भूमि आबंटित की जा सकेगी;
(iv) खरीफ, 1968 से पहले भूमि मालिक द्वारा अधिशेष क्षेत्र पर बसाया गया एक किरायेदार, जो -

(ए) पंजाब कानून की धारा 2 के खंड (9) या उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट श्रेणी के भूमि मालिक का संबंध; या

(ख) पीपीएसयू विधि की धारा 52 के साथ पठित धारा 2 के खंड (छ) के उपखंड (ii) के अधीन बनाए गए नियम में विनिर्दिष्ट श्रेणी के उनके भूस्वामी के संबंधी; या

(ग) इस अधिनियम की धारा 31 के साथ पठित धारा 3 के खंड (ओं) के अधीन बनाए गए नियम में विनिर्दिष्ट श्रेणी का भूस्वामी का संबंध,

धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के दो हेक्टेयर की सीमा तक भूमि या समतुल्य मूल्य की भूमि इस शर्त के अधीन रहते हुए आबंटित की जा सकेगी कि इस प्रकार आबंटित भूमि और उसके द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो, धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट श्रेणी की दो हेक्टेयर भूमि या समतुल्य मूल्य की भूमि से अधिक न हो; और

(v) किसी अन्य पात्र श्रेणी के व्यक्ति को धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के दो हेक्टेयर की सीमा तक भूमि या समतुल्य मूल्य की भूमि का आबंटन इस शर्त के अधीन किया जा सकता है कि इस प्रकार आबंटित भूमि और उसके द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो, धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट श्रेणी की दो हेक्टेयर भूमि या समतुल्य मूल्य की भूमि से अधिक न हो। "

वास्तव में राज्य सरकार द्वारा एक योजना तैयार की गई है। योजना के खंड (4) में अधिशेष भूमि के आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणियों की गणना की गई है। 'श्रेणी ए' पंजाब कानून या पेप्सू कानून, जैसा भी मामला हो, के तहत किरायेदार के अनुमेय क्षेत्र के रूप में घोषित एक किरायेदार की भूमि है। 'श्रेणी बी' एक किरायेदार है जिसे पंजाब कानून या पेप्सू कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिशेष क्षेत्र में भूमि आवंटित और कब्जा दिया गया था और उसके पास वही है। श्रेणी सी, डी और ई किरायेदारों के अन्य वर्ग हैं, और श्रेणी एफ, जी, एच और आई आवंटन के हकदार व्यक्तियों के अन्य वर्ग हैं। योजना का खंड (7) आबंटन के सिद्धांतों और प्रक्रिया को निर्धारित करता है। खंड (7) के उपखंड (i) में प्रावधान हैः "पात्र श्रेणियों के बीच प्राथमिकता उसी क्रम में होगी जिसमें इन्हें पैराग्राफ 4 में सूचीबद्ध किया गया है, अर्थात, श्रेणी ए श्रेणी बी पर प्राथमिकता लेगी और श्रेणी बी श्रेणी सी पर प्राथमिकता लेगी। खंड (7) के उपखंड (ii) में यह प्रावधान हैः "श्रेणी 'ए' के पात्र व्यक्तियों को उनके द्वारा धारित क्षेत्रों में से इस अधिनियम के तहत अनुमेय क्षेत्र की सीमा तक भूमि आवंटित की जाएगी।" इसी तरह, उपखंड (iii) में प्रावधान किया गया है कि "श्रेणी बी के योग्य व्यक्तियों को उनके द्वारा धारित क्षेत्रों का आवंटन किया जाएगा।" इस प्रकार यह देखा गया है कि धारा 4 के तहत किरायेदार के अनुमेय क्षेत्र का निर्धारण व्यर्थ की कवायद नहीं है। यह योजना के तहत उसके द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र से बाहर इस अधिनियम के तहत अनुमेय क्षेत्र की सीमा तक उसे भूमि सुरक्षित करने का इरादा है। योजना के तहत आवंटन का अंतिम प्रभाव उन किरायेदारी अधिकारों को स्वामित्व के अधिकारों में बदलना होगा जो उनके पास पहले भूमि में थे।

(12) कुछ रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के वकील श्री के. पी. भंडारी ने तर्क दिया कि धारा 12 (3) राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे है क्योंकि यह अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत राज्य सरकार में निहित भूमि के लिए मुआवजा प्रदान नहीं करता है। हालाँकि, उन्होंने संभवतः 1976 के अधिनियम XVII को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के कारण तर्क को और विस्तार से नहीं बताया।

श्री भंडारी का मुख्य निवेदन धारा 12 (4) के खिलाफ था जो इस प्रकार हैः -

" इस अधिनियम के तहत अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण करने के उद्देश्य से, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा नियत दिन के बाद प्राप्त और अधिशेष क्षेत्र को कम करने के प्रभाव वाले निर्णय, डिक्री या आदेश को अनदेखा किया जाएगा। "

श्री भंडारी ने कहा कि न्यायालय के निर्णय को अमान्य या अप्रभावी घोषित करना विधानमंडल की क्षमता से परे है क्योंकि यह न्यायिक कार्य पर अतिक्रमण करेगा जो हमारे संविधान के तहत, विधानमंडल को करने से वर्जित है। उन्होंने जनपद सभा छिंदवाड़ा बनाम सी. पी. सिंडिकेट A.I.R. 1971 S.C. 57. , तमिलनाडु राज्य बनाम रायप्पा A.I.R. 1971 S. C. 231. और इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण A.I.R. 1975 S.C. 2299 के प्रसिद्ध निर्णयों पर भरोसा किया। प्रतिपादित सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है लेकिन वर्तमान मामले में इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है। धारा 12 (4) किसी न्यायालय के किसी निर्णय को अपास्त करने या उलटने के लिए अभिप्रेत नहीं है। इसका उद्देश्य किसी निर्णय को अमान्य घोषित करना नहीं है। इसमें केवल यह घोषणा नहीं की गई है कि किसी व्यक्ति के अधिशेष क्षेत्र को कम करने के प्रभाव वाली डिक्री को अगर नियत दिन के बाद बनाया जाता है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। जिस प्रकार अधिशेष क्षेत्र निर्धारित करने के उद्देश्य से अंतरविवोस हस्तांतरण को, जो प्रामाणिक नहीं है, नजरअंदाज किया जाना चाहिए, उसी प्रकार यह अधिनियमित किया गया है कि अधिशेष क्षेत्र को कम करने के प्रभाव वाले निर्णय को भी नजरअंदाज किया जाना चाहिए। विधायिका ने मिलीजुली फरमानों के आधार पर प्रामाणिक रूप से प्राप्त फरमानों के पक्ष में किसी भी कथन के लिए इस साधारण कारण का प्रतिपादन नहीं किया है कि राजस्व अधिकारियों के लिए इस प्रश्न पर जाना अनुचित होगा कि क्या सिविल कोर्ट की डिक्री मिलीजुली है। धारा 12 (4) का एकमात्र प्रभाव यह है कि नियत दिन के बाद प्राप्त डिक्री को किसी व्यक्ति के अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण करने में ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। धारा 12 (4) किसी अन्य तरीके से निर्णय की वैधता को प्रभावित नहीं करती है। उन व्यक्तियों के अधिकार जो निर्णय के पक्षकार हैं, जैसे कि वे हैं, आपस में अप्रभावित रहते हैं।

(13) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील में से एक, श्री एम.एस. रत्ता द्वारा यह आग्रह किया गया था कि 1976 के अधिनियम 40 द्वारा किया गया धारा 12(1) का संशोधन बुरा था, क्योंकि इसमें मुआवजे के लिए कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने आग्रह किया कि वह प्रश्न उठाने का अधिकार था क्योंकि 1976 के अधिनियम 40 को नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। 1976 के अधिनियम 40 द्वारा संशोधित किए जाने से पहले धारा 12 जैसी थी, उसमें कहा गया है कि "एक भूस्वामी का अधिशेष क्षेत्र, जिस तारीख को राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से उस पर कब्ज़ा लिया जाता है, उसे अर्जित माना जाएगा राज्य सरकार द्वारा, इसके बाद प्रदान की गई राशि के भुगतान पर एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए।" 1976 के अधिनियम 40 द्वारा, शब्द "जिस तारीख को राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से कब्जा लिया जाता है, उसे इसके बाद प्रदान की गई राशि के भुगतान पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित माना जाएगा" को हटा दिया गया और शब्द "उस तारीख से जब इसे इस रूप में घोषित किया गया है, राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित किया गया माना जाएगा" प्रतिस्थापित किया गया। श्री रत्ता के अनुसार, "इसके बाद प्रदान की गई राशि का भुगतान" शब्दों को हटाने से पता चलता है कि मुआवजा देय नहीं था। निवेदन में कोई भी तथ्य नहीं है। मुआवज़ा उसी धारा में प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है जो भूमि को सरकार में निहित करने का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 16 स्पष्ट रूप से तालिका में दर्शाई गई दरों पर मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करती है। मुआवज़े के भुगतान के स्पष्ट प्रावधानों के सामने, यह भुगतान करने का कोई मतलब नहीं है कि मुआवज़ा क़ानून द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।

(14) विद्वान वकील श्री ग्रेवाल ने तर्क दिया कि हरियाणा अधिनियम की धारा 9 (4) (सी), जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि एक परिवार के मामले में, घोषणा पति द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के प्रतिकूल थी, जो एक महिला को उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति प्राप्त करने पर पूर्ण अधिकार प्रदान करती है। इस प्रस्तुतीकरण में कोई सार नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदू पुरुषों और महिलाओं के स्वामित्व वाली संपत्ति की सफलता से संबंधित है। हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा घोषित उत्तराधिकार के कानून को प्रभावित या प्रभावित नहीं करता है। जो भी हो, कोई तिरस्कार नहीं है। एक बार जब कोई व्यक्ति संपत्ति में सफल हो जाता है, तो उसके बाद वह किसी अन्य व्यक्ति की तरह उसी कानून के अधीन संपत्ति रखता है जिसके वे अधीन हैं और जिसे समय-समय पर बनाया जा सकता है। परिवार के सदस्यों द्वारा धारित कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा से संबंधित कानून को संभवतः उत्तराधिकार से संबंधित कानून नहीं कहा जा सकता है। हम इस प्रश्न पर और विस्तार करना अनावश्यक समझते हैं।

(15) श्री नागपाल ने आग्रह किया कि किस अधिशेष क्षेत्र को घोषित किया जाना है, इसके संदर्भ में कोई तिथि निर्दिष्ट नहीं की गई थी। तर्क पूरी तरह से आधारहीन है। धारा 7 में स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति नियत दिन को या उसके बाद हरियाणा राज्य के भीतर अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि में भूमि स्वामी या किरायेदार के रूप में या कब्जे वाले गिरवीदार के रूप में या आंशिक रूप से एक क्षमता में और आंशिक रूप से किसी अन्य भूमि में धारण करने का हकदार नहीं होगा। नियुक्त दिवस को धारा 3 (सी) में 24 जनवरी, 1971 के रूप में परिभाषित किया गया है। श्री नागपाल का एक अन्य निवेदन था कि धारा 8 (1) के परंतुक में "लाभ" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया था। हमें नहीं लगता कि विधायिका के लिए एक क़ानून में होने वाली प्रत्येक अभिव्यक्ति को परिभाषित करना आवश्यक था। यह अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरणों के लिए है कि वे व्याख्या के प्रसिद्ध सिद्धांतों के साथ अभिव्यक्ति की व्याख्या करें।

(16) कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील श्री एच. एस. वासु ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल एक बड़े जमींदार से बदले में लिए गए थे, जिनकी जमीन को सरकार ने पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट के संचालन से छूट दी थी ताकि जमीन को बगीचे के रूप में विकसित किया जा सके और उनके मामलों में सरकार को उनके खिलाफ हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट लागू करने से रोक दिया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें बेची गई जमीन पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट के प्रावधानों के तहत जमींदार के अधिशेष क्षेत्र में शामिल थी। श्री वासू के अनुसार, सरकार द्वारा दी गई छूट के कारण, विक्रेताओं ने नियमों के तहत सरकार द्वारा निर्धारित सभी कठोर शर्तों का पालन करते हुए बागों के विकास के लिए भारी राशि का निवेश किया था। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी पहले की प्रतिबद्धता पर कायम रहने के लिए बाध्य है और न्यायसंगत रोक के सिद्धांत से यह दावा करने से वर्जित है कि हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट की धारा 12 के तहत भूमि सरकार में निहित हो गई है। उन्होंने भारत संघ बनाम भारत-अफगान एजेंसियों लिमिटेड A.I.R. 1968 S.C. 718 के प्रसिद्ध मामले पर भरोसा किया। श्री वासु के निवेदन का सरल उत्तर यह है कि विधानमंडल या उसके जनादेश के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है। केरल राज्य बनाम ग्वालियर रेयॉन सिल्क एम. एफ. जी. (डब्ल्यूवीजी।) कंपनी लिमिटेड आदि A.I.R. 1973 S.C. 2734, केरल सरकार ने कंपनी के साथ एक समझौता किया था कि वह साठ वर्षों की अवधि के लिए निजी वनों के अधिग्रहण के लिए कानून नहीं बनाएगी यदि कंपनी कच्चे माल की आपूर्ति के उद्देश्यों के लिए वन भूमि खरीदती है। कंपनी ने 75,00,000 रुपये में तीस हजार एकड़ निजी वन खरीदे। यह तर्क दिया गया था कि कानून नहीं बनाने का समझौता राज्य के खिलाफ न्यायसंगत अवरोध के रूप में काम करेगा और इसलिए केरल निजी वन (वेस्टिंग एंड असाइनमेंट) अधिनियम, 1971 को कंपनी के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया :-

उन्होंने कहा, "हमें नहीं लगता कि सरकार का समझौता इस विषय पर कानून बनाने से कैसे रोक सकता है। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि सरकार द्वारा अपनी विधायी शक्तियों का सार्वजनिक भलाई के लिए उपयोग करने के लिए समर्पण कंपनी का लाभ नहीं उठा सकता है या सरकार के खिलाफ न्यायसंगत अवरोध के रूप में काम नहीं कर सकता है। "

इसी प्रकार, माथरा प्रसाद एंड संस बनाम पंजाब राज्य, A.I.R. 1962 S.C. 745 में सरकार ने एक प्रेस नोट द्वारा घोषणा की थी कि तंबाकू की बिक्री के संबंध में कोई बिक्री कर नहीं लगाया जाएगा जो तंबाकू विक्रय शुल्क के अंतर्गत आता है और जो भी कर पहले से ही एक व्यापारी से वसूल किया गया है, उसे वापस कर दिया जाएगा। प्रेस नोट के बावजूद बिक्री कर लगाने के लिए आगे बढ़ रहे आबकारी और कराधान अधिकारी के खिलाफ निषेध की एक रिट मांगी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा: -

"कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है। यदि कानून यह माँग करता है कि एक निश्चित कर एकत्र किया जाए, तो इसे नहीं छोड़ा जा सकता है, और कोई भी आश्वासन कि इसे एकत्र नहीं किया जाएगा, राज्य सरकार को बाध्य नहीं करेगा, जब भी उसने इसे एकत्र करने का विकल्प चुना।"

इसी तरह का निर्णय आबकारी आयुक्त, यू. पी. बनाम राम कुमार A.I.R. 1976 S.C. 2237 में लिया गया है। न्यायसंगत रोक का पूरा सवाल, इस अदालत की एक डिवीजन बेंच द्वारा बहुत विस्तार से किया गया था, जिसमें हममें से एक पंजाब राज्य बनाम अमृत बनस्पति कंपनी लिमिटेड (एल.पी.ए. 368—75 का निर्णय 25 जनवरी 1977 को हुआ) में सदस्य था और यह बताया गया था कि संसद को कानून बनाने से रोकने या संसद के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते समय सरकार को कार्यकारी क्षमता में पहले किए गए वादों के विपरीत अधीनस्थ कानून बनाने या सरकार को संसद के जनादेश को बनाने से रोकने के लिए कभी भी रोक नहीं लगाई जा सकती है। यह भी बताया गया कि न्यायसंगत रोक का सिद्धांत इस तरह काम नहीं कर सकता था कि सरकार को संसद के एक अधिनियम द्वारा उस पर लगाए गए दायित्वों का निर्वहन करने से रोका जा सके या सरकार को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा सके जो कानून द्वारा निषिद्ध था या जो स्पष्ट विधायी नीति के खिलाफ था। इसलिए हम न्यायसंगत बहिष्कार के सिद्धांत पर आधारित श्री वासु के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि यह कहना सही नहीं है कि किसी भी भूमि को पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट के संचालन से छूट दी गई थी। वास्तव में, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो सरकार को किसी भी भूमि को अधिनियम के संचालन से छूट देने में सक्षम बनाता हो। हालाँकि, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ़ लैंड टेन्योर रूल्स के नियम 8 ने एक भूमि मालिक को इस आधार पर अपने अधिशेष क्षेत्र के उपयोग से छूट के लिए समिति को आवेदन करने में सक्षम बनाया कि उसका अधिशेष क्षेत्र चाय-एस्टेट के तहत था या एक अच्छी तरह से संचालित खेत का हिस्सा था। नियम 10 के तहत समिति को नियम 11 के अनुसार आवंटित अंकों के आधार पर चाय-संपदा या अच्छी तरह से संचालित खेत के पूरे या हिस्से को विस्थापित किरायेदारों के पुनर्वास के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिशेष क्षेत्र से बाहर करने का अधिकार दिया गया था। समिति को हर तीन साल के बाद वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा करने का भी अधिकार दिया गया था। इस प्रकार नियम एक बड़े जमींदार के अधिशेष क्षेत्र से एक अच्छी तरह से संचालित खेत को बाहर नहीं करते थे, बल्कि केवल निष्कासित किरायेदारों के पुनर्वास के लिए इसका उपयोग करने से रोकते थे। भूमि ने पूरे अधिशेष क्षेत्र के अपने चरित्र को बनाए रखा। हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट के पारित होने पर, यह अधिनियम की धारा 12 के तहत राज्य सरकार में निहित हो गया। यह सच है कि हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स अधिनियम की धारा 12 उन व्यक्तियों पर बहुत मेहनत कर सकती है जिन्होंने एक बड़े भूस्वामी से भूमि खरीदी है और इस विश्वास में भूमि को बगीचे के रूप में विकसित करने में बड़ी राशि का निवेश किया है कि भूमि को बड़े भूस्वामी के अधिशेष क्षेत्र के रूप में नहीं माना जाएगा। लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिसे पीड़ित लोगों को कठिनाई से राहत देने के लिए उचित कार्रवाई के लिए सरकार के साथ उठाना होगा। हम अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।

(17) अब हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं जो श्री भंडारी द्वारा हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स अधिनियम की धारा 20-ए की संवैधानिक वैधता पर उठाया गया था, जो वित्तीय आयुक्त के अलावा किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण के समक्ष किसी भी कानूनी व्यवसायी की उपस्थिति को प्रतिबंधित करता है। यह तर्क दिया गया था कि धारा 20-ए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 के प्रतिकूल थी, जो यह घोषणा करती है कि प्रत्येक अधिवक्ता जिसका नाम सामान्य सूची में दर्ज किया गया है, (i) उच्चतम न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में, (ii) किसी अधिकरण या साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्तियों के समक्ष, और (iii) किसी अन्य प्राधिकारी या प्रतिव्यक्ति के समक्ष, जिसके समक्ष ऐसा अधिवक्ता तत्काल किसी विधि द्वारा या उसके अधीन वकालत करने का हकदार है, वकालत करने के अधिकार का हकदार होगा। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट के तहत गठित प्राधिकरण कानूनी रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत हैं (अधिनियम की धारा 20 के तहत) । इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि लेकिन अधिनियम की धारा 20-ए के लिए, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 (ii) के आधार पर अधिनियम के तहत काम करने वाले किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का हकदार होगा। श्री भंडारी का तर्क था कि अधिवक्ता अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टियों 77 और 78 के अनुसरण में संसद द्वारा बनाया गया एक कानून था और इसके पूर्व, राज्य विधानमंडल इसके प्रतिकूल कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं था। यह तर्क दिया गया था कि धारा 20-ए को संविधान के अनुच्छेद 254 (2) द्वारा नहीं बचाया जाएगा क्योंकि अधिवक्ता अधिनियम समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले के संबंध में बनाया गया कानून नहीं था। श्री भंडारी ने ओ. एन.

मोहिंद्रू बनाम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, A.I.R. 1960 S.C, 888 मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पूरा भरोसा जताया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या अधिवक्ता अधिनियम की धारा 38, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपीलीय अधिकारिता प्रदान करती है, संविधान के अनुच्छेद 138 (2) से परे थी। अनुच्छेद 138 (1) संघ सूची के किसी भी मामले के संबंध में संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायशास्त्र के विस्तार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 138 (2) किसी भी मामले के संबंध में संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के विस्तार का प्रावधान करता है जिस पर भारत सरकार और किसी भी राज्य की सरकार विशेष रूप से सहमत हो सकती है। यदि अधिवक्ता अधिनियम पूरी तरह से संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो अधिनियम के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यदि यह सूची III के अंतर्गत आता है-तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समझौते के अभाव में, अधिनियम अमान्य होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिवक्ता अधिनियम एक समग्र विधि थी जो आंशिक रूप से सूची I की प्रविष्टि 77 और 78 के अधीन और आंशिक रूप से सूची III की प्रविष्टि 26 में आती है। उच्चतम न्यायालय ने सूची-I की प्रविष्टि 77 और 78 और सूची-III की प्रविष्टि 26 का उल्लेख करने के पश्चात् निम्नलिखित मत व्यक्त कियाः -

"सूची I में प्रविष्टियाँ 77 और 78, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के संविधान और संगठन से निपटने के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष वकालत करने के हकदार व्यक्तियों से भी संबंधित हैं। दो प्रविष्टियों के इस भाग से पता चलता है कि जहां तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष वकालत करने के हकदार व्यक्तियों का संबंध है, उनके संबंध में कानून बनाने की शक्ति सूची III में प्रविष्टि 26 में व्यवसायों से संबंधित सामान्य शक्ति से बनाई गई है और इसे संसद के लिए अपवादात्मक क्षेत्र बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में वकालत करने के हकदार लोगों को छोड़कर, बाकी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, व्यवसायियों को अभी भी सूची III की प्रविष्टि 26 के तहत बनाए रखा गया प्रतीत होता है। कानूनी पेशे के संबंध में कानून बनाने की शक्ति अभी भी प्रविष्टि 26 के क्षेत्र में किस हद तक बनी हुई है, यह वर्तमान में हमारे सामने प्रश्न नहीं है और इसलिए, इस अपील में इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है।"

उच्चतम न्यायालय ने तब अधिनियम के उद्देश्य और धारा 30 सहित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया। तब इस प्रकार कहा गया-

"हालांकि यह अधिनियम कानूनी व्यवसायियों से संबंधित है, लेकिन इसके सार और सार में यह एक ऐसा अधिनियम है जो स्वयं अधिवक्ताओं की योग्यता, नामांकन, अभ्यास करने के अधिकार और अनुशासन से संबंधित है। जैसा कि अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया है कि एक बार जब कोई व्यक्ति राज्य बार काउंसिल में से किसी एक द्वारा नामांकित हो जाता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में वकालत करने का हकदार हो जाता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अधिनियम एक सामान्य बार का निर्माण करता है, जिसके सभी सदस्य एक वर्ग के होते हैं, अर्थात् अधिवक्ता। चूंकि नामांकित किए गए सभी लोगों को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में वकालत करने का अधिकार है, इसलिए अधिनियम एक विधान है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष वकालत करने के हकदार व्यक्तियों से संबंधित है। अतः अधिनियम को सूची-I की प्रविष्टियों 77 और 78 के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। चूंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में वकालत करने के हकदार लोगों से संबंधित विधान की शक्ति को सूची III की प्रविष्टि 26 में कानूनी और अन्य व्यवसायों के संबंध में) विधान करने की सामान्य शक्ति से अलग किया गया है, इसलिए यह कहना एक त्रुटि है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने किया था, कि अधिनियम एक समग्र विधान है जो आंशिक रूप से सूची I की प्रविष्टियों 77 और 78 और आंशिक रूप से सूची III की 26 के तहत आता है। "

इस प्रकार, यह उच्चतम न्यायालय का मत प्रतीत होता है कि सूची I की प्रविष्टियां 77 और 78, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष अभ्यास करने के हकदार व्यक्तियों से संबंधित हैं, अर्थात्, प्रविष्टियां न केवल उन लोगों से संबंधित हैं जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अभ्यास करने के हकदार हैं, बल्कि उनसे संबंधित अन्य सभी मामलों जैसे कि उनकी योग्यता, विवेकाधिकार, अन्यत्र अभ्यास करने के अधिकार सहित अधिकार आदि

से भी संबंधित हैं। उस दृष्टिकोण से, एक अधिवक्ता का अधिकार जिसका नाम सामान्य सूची में किसी भी न्यायाधिकरण के समक्ष वकालत करने के लिए दिखाई देता है या साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति, राज्य के कानून द्वारा छीन नहीं लिया जा सकता है। इस हद तक कि धारा 20-क किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष अधिवक्ताओं की उपस्थिति को प्रतिबंधित करती है, इसे अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 के प्रतिकूल माना जाना चाहिए और इसलिए अमान्य है। हम यह जोड़ना चाहेंगे कि हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट एक जटिल कानून है और विशेषज्ञ कानूनी सहायता के बिना आम लोगों के लिए इसके कुछ प्रावधानों को समझना वास्तव में मुश्किल होगा। लेकिन यह आवश्यक है कि जिन लोगों को कानूनी सहायता की आवश्यकता है ताकि वे अपने मामले को ठीक से सामने रख सकें, उन्हें उस सहायता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मामले उन मामलों की तरह नहीं हैं जो श्रम न्यायालय के समक्ष आते हैं, जहां यदि कानूनी व्यवसायियों को उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है, तो एक गरीब मजदूर जो एक वकील की सेवाओं को शामिल करने में असमर्थ है, खुद को प्रबंधन द्वारा नियुक्त एक दृढ़ अधिवक्ता के खिलाफ खड़ा कर सकता है। ऐसी स्थिति संभवतः सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट के तहत मामलों में उत्पन्न नहीं हो सकती है। हालांकि धारा 20-ए को लागू करने में विधायी विवेक पर सवाल उठाना हमारा काम नहीं है, हम प्रावधान के लिए कोई कारण खोजने में असमर्थ हैं। शायद यह बुद्धि द्वारा व्यक्त निराधार अविश्वास पर आधारित है:

“In the heels of the higgling lawyers,

Too many slippery ifs and buts and howevers,

Too much hereinbefore provided whereas,

Too many doors to go in and out of, When the lawyers are through What is there left Bob ?

Can a mouse nibble at it

And find enough to fasten a tooth in ? ”

(18) पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, सभी रिट याचिकाओं को निम्नलिखित निर्देशों के अधीन खारिज कर दिया जाता हैः -

जिन याचिकाकर्ताओं ने अब तक अपनी घोषणाएं दाखिल नहीं की हैं, उन्हें अपनी घोषणाएं दायर करने के लिए आज से एक महीने का समय दिया जाता है।

2. जिन याचिकाकर्ताओं ने अपनी घोषणाएं दायर की हैं, वे अधिनियम के तहत उनके लिए उपलब्ध उपायों का अनुसरण कर सकते हैं।

3. सभी घोषणाओं को इस फैसले के आलोक में कानून के अनुसार अधिनियम के तहत गठित अधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

4. अधिनियम की धारा 22 के तहत बेदखल किए जाने की आशंका वाले लेकिन धारा 8 के संरक्षण के हकदार होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं को आज से पंद्रह दिन का समय दिया जाता है ताकि वे कलेक्टर के समक्ष सुरक्षा की मांग करते हुए आवेदन दायर कर सकें। इस बीच उनके कब्जे को बाधित नहीं किया जाएगा।

5. धारा 20-ए को लागू नहीं किया जाएगा ताकि अधिवक्ताओं को अधिनियम के तहत काम करने वाले किसी भी प्राधिकरण या अधिकारी के सामने पेश होने से रोका जा सके।

भूपिंदर सिंह ढिल्लों, न्यायमूर्ति -मैं सहमत हूँ,

गुरनाम सिंह, न्यायमूर्ति -मैं सहमत हूँ।

अजीत सिंह बैंस, न्यायमूर्ति -में भी सहमत हूँ।

हरबंस लाल, न्यायमूर्ति -मैं सहमत हूँ।

(19) निर्णय तैयार किए जाने के बाद, यह हमारे संज्ञान में लाया गया कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा, 30 अभी तक प्रवृत्त नहीं हुई है। हालाँकि, इससे हरियाणा अधिनियम की धारा 20-ए की वैधता के बारे में हमारे निष्कर्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 लागू नहीं हो जाती, तब तक अधिवक्ता अधिनियम की धारा 50 (3) (सी) के आधार पर भारतीय बार काउंसिल अधिनियम की धारा 14 लागू रहेगी। अब भारतीय बार काउंसिल अधिनियम की धारा 14 (1) अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 के समान है और निम्नानुसार हैः

"14. अधिवक्ताओं का अभ्यास करने का अधिकार - (1) एक अधिवक्ता वकालत करने के अधिकार के रूप में हकदार होगा -

(क) धारा 9 की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जिसके उच्च न्यायालय में वह अधिवक्ता है; और

(ख) उपधारा (2) द्वारा या किसी अन्य न्यायालय में और साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकरण या व्यक्ति के समक्ष तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित किए बिना; और

(ग) किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष, जिसके समक्ष ऐसा अधिवक्ता तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या उसके अधीन वकालत करने का हकदार है।"

भारतीय बार काउंसिल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 1 (2) 2 (एल) (ए) 2 (1) (सी) 3,8,9,10,14,15 की जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भारतीय बार काउंसिल अब्ट मुख्य रूप से उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस करने के हकदार अधिवक्ताओं की योग्यता, नामांकन, प्रैक्टिस करने का अधिकार और अनुशासन के साथ जुड़ा हुआ है, भले ही अधिवक्ता अधिनियम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस करने के हकदार अधिवक्ताओं की योग्यता, नामांकन, प्रैक्टिस करने का अधिकार और अनुशासन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिवक्ता अधिनियम के संदर्भ में और हमारे द्वारा अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 के संदर्भ में जो कुछ भी कहा गया है वह भारतीय बार काउंसिल अधिनियम की धारा 14 के समान ही लागू होता है। इसलिए हरियाणा अधिनियम की धारा 20-ए असंवैधानिक है।

भूपिंदर सिंह ढिल्लों, न्यायमूर्ति -मैं सहमत हूँ,

गुरनाम सिंह, न्यायमूर्ति -मैं सहमत हूँ।

अजीत सिंह बैंस, न्यायमूर्ति -में भी सहमत हूँ।

हरबंस लाल, न्यायमूर्ति -मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रजत कुमार कनौजिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद,हरियाणा